

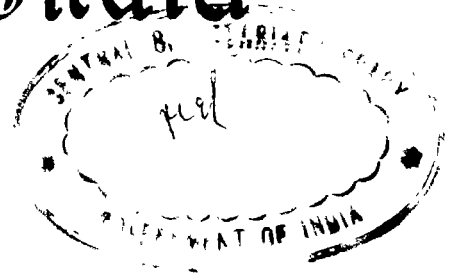


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 161]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 11, 2000/फाल्गुन 21, 1921

No. 161]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 11, 2000/PHALGUNA 21, 1921

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2000

सा. का. नि. 243(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर भर्ती की रीति को नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव) नियम, 2000 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन, इन नियमों के अधीन पदों पर नियुक्ति करने के लिए, प्राधिकृत प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (ख) “नियत दिन” से वह दिन अभिप्रेत है जिसको ये नियम प्रवृत्त होंगे;
- (ग) “अनुमोदित सेवा” से ग्रेड में भर्ती किसी अधिकारी के संबंध में उस ग्रेड में की गई नियमित सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत हैं इसके अन्तर्गत अनुपस्थिति की वह अवधि अवधियां भी हैं जिनके दौरान वह उस ग्रेड में नियमित आधार पर पद धारित करता किन्तु अवकाश पर रहने या अन्यथा के कारण ऐसा पद धारित करने के लिए उस वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन से, जिसके लिए भर्ती की गई थी, उपलब्ध नहीं था :
परन्तु जहां नियुक्ति पर पद ग्रहण से तीन महीने से अनधिक का विलम्ब नहीं हुआ है वहां ऐसे विलम्ब अधिकारी के किसी व्यतिक्रम के कारण नहीं होना चाहिए।
- (घ) “केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा” से केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 के अधीन गठित केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा अभिप्रेत है;
- (ङ) “काडर” से पदों का ऐसा समूह अभिप्रेत है जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मंत्रालय या विभाग में ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड में सम्मिलित है;
- (च) “आयोग” से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
- (छ) “निजी सचिव ग्रेड” से केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1979 का निजी सचिव ग्रेड “क” अभिप्रेत है;
- (ज) “अनुसूची” से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (झ) “विभागीय प्रोन्नति समिति” से नियम 5 के अधीन गठित विभागीय प्रोन्नति समिति अभिप्रेत है;

- (ज) "चयन सूची" से नियम 7 के उपनियम (2) के अनुसार तैयार की गई चयन सूची अभिप्रेत है;
- (ट) "चयन सूची वर्ष" से किसी वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर आगामी वर्ष की जून की 30 तारीख तक की अवधि अभिप्रेत है;

3. गठन, प्राधिकृत संख्या और वेतनमान—

- (1) ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव का पद राजपत्रित, अनुसचिवीय होगा और यह केन्द्रीय सिविल सेवा ग्रुप "क" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यह केन्द्रीय सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित केन्द्रीयकृत काडर होगा।
- (2) नियत से ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड के पदों की प्राधिकृत संख्या और मंत्रालय या विभाग जिन्हें ये नियम लागू होते हैं वे होंगे जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए जाएं :
- परन्तु नियत दिन के पश्चात् ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड में पदों की प्राधिकृत संख्या और मंत्रालय और विभाग जिन्हें ये नियम लागू होते हैं उतने होंगे जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अवधारित किए जाएं।
- (3) ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड का वेतनमान 12000-375-16500 रुपए होगा।

4. भर्ती की रीति और पात्रता :

ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव के पदों पर भर्ती उन अधिकारियों में से गुणागुणा के आधार पर चयन के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा की जाएगी, जिन्होंने निजी सचिव ग्रेड "क" (वेतनमान 10,000-15,200 रु.) में अनुमोदित सेवा के पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं।

5. विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन

- (1) भारत सरकार का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, समय-समय पर, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन करेगा—
- | | |
|---|---------|
| (क) आयोग का अध्यक्ष या सदस्य | अध्यक्ष |
| (ख) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का भारसाधक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का अपर सचिव | सदस्य |
| (ग) भारत सरकार के दो अन्य अपर सचिव | सदस्य |
- (2) यथास्थिति, आयोग का अध्यक्ष या सदस्य विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

6. ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव की नियुक्तियां—

ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड में नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस क्रम में की जाएंगी जिसमें तत्समय प्रवृत्त चयन सूची में उन अधिकारियों के नाम उपसंज्ञात होते हैं।

7. सूचियां का बनाया जाना—

- (1) केन्द्रीय सरकार का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग उस ग्रेड की चयन सूची के आधार पर निजी सचिव ग्रेड "क" (10000—15200 रु.) की एक केन्द्रीयकृत ज्येष्ठता सूची तैयार करेगा।
- (2) विभागीय प्रोन्नति समिति, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में रिक्तियों को भरने के लिए, अधिकारियों की एक चयन सूची तैयार करेगी।

8. चयन सूची का अनुरक्षण —

- (1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, चयन सूची में सम्मिलित कोई अधिकारी, ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड में अपनी नियुक्ति होने तक, उसमें बना रहेगा।
- (2) चयन सूची में सम्मिलित ऐसे अधिकारी जिन्हें ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड में नियुक्त नहीं किया जा सका है या जो रिक्तियां न होने के कारण वहां से प्रतिवर्तित कर दिए गए हैं, नियम 9 में अंतर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, चयन सूची में सम्मिलित रहेंगे और चयन सूची में उन्हें दी गई ज्येष्ठता को प्रतिधारित करेंगे।

9. चयन सूची से नाम का हटाया जाना—

निम्नलिखित प्रवर्ग के व्यक्तियों के नाम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा चयन सूची से हटाए जाएंगे :—

- (क) ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त व्यक्ति,
- (ख) किसी अन्य सेवा या पदों पर स्थानांतरित व्यक्ति,
- (ग) ऐसे व्यक्ति जो मर गए हैं, सेवा से निवृत्त हो गए हैं या जिनकी सेवाएं अन्यथा समाप्त कर दी गई हैं।

10. अनुदेश—केन्द्रीय सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में इन नियमों से अनसंगत इन नियमों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए ऐसे विषयों की बाबत अनुदेश जारी कर सकेगी जिनके लिए उपबंध किया जाना आवश्यक या समीचीन है।

11. निरर्हता—वह व्यक्ति—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

12. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

13. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

14. **निर्वचन**—जहां इन नियमों के किसी उपबंध या उनके अधीन जारी अनुदेशों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह विषय केन्द्रीय सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

[सं. 10/02/99-के.से.-II]

कर्ण सिंह, निदेशक (के. से.-II)

अनुसूची-I

[देखिए नियम 3(1)]

(क) प्राधिकृत संख्या—58

(ख) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के सहभागी कार्यालयों सहित सहभागी मंत्रालयों और विभागों की सूची

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग
1.	कृषि तथा सहकारिता विभाग
2.	नागर विमानन मंत्रालय
3.	कोयला मंत्रालय
4.	वाणिज्य मंत्रालय
5.	कम्पनी कार्य विभाग
6.	उपभोक्ता कार्य विभाग
7.	रक्षा मंत्रालय
8.	शिक्षा विभाग
9.	पर्यावरण और वन मंत्रालय
10.	व्यय विभाग
11.	उर्वरक विभाग
12.	खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग
13.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
14.	गृह मंत्रालय
15.	औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन विभाग
16.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय
17.	श्रम मंत्रालय
18.	विधि कार्य विभाग
19.	खान विभाग
20.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
21.	योजना आयोग
22.	डाक विभाग
23.	ऊर्जा मंत्रालय
24.	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय
25.	विज्ञान तथा तकनीकी मंत्रालय
26.	सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय
27.	इस्पात विभाग
28.	आपूर्ति विभाग
29.	भूतल परिवहन मंत्रालय
30.	दूरसंचार विभाग
31.	संघ लोक सेवा आयोग
32.	शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय
33.	जल संसाधन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2000

G.S.R. 243(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Principal Private Secretary in the Central Secretariat Stenographers' Service, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Secretariat Stenographers' Service (Senior Principal Private Secretary) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "appointing authority" means the authority empowered under the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 to make appointments to the posts under these rules;

(b) "appointed day" means the date on which these rules come into force;

(c) "approved service" in respect of an officer recruited to the grade means the period or periods of regular service rendered in the grade, including period or periods of absence during which he would have held post on regular basis in the grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of July of the year for which the recruitment was made :

Provided that where there is a delay of more than three months in joining on appointment, such delay should not be due to any fault of the officer.

(d) "Central Secretariat Stenographers' Service" means the Central Secretariat Stenographers' Service constituted under the Central Secretariat Stenographers' Service Rules, 1969;

(e) "Cadre" means the group of posts included in the Senior Principal Private Secretary Grade in any of the Ministries or Departments specified in Schedule-I ;

(f) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(g) "Private Secretary Grade" means the Private Secretary Grade 'A' of the Central Secretariat Stenographers' Service Rules, 1989,

(h) "Schedule" means a schedule to these rules;

(i) "Departmental Promotion Committee" means the Departmental Promotion Committee constituted under rule 5;

(j) "select list" means the select list prepared in accordance with sub-rule (2) of Rule 7;

(k) "Select list year" means the period commencing from the 1st day of July of any year to the 30th day of June of the following year.

3 **Composition, Authorised strength and the Scale of pay.**—(1) The post of the Senior Principal Private Secretary shall be gazetted, ministerial and shall be classified as Central Civil Service Group 'A'. This shall be a centralised cadre to be controlled by the Central Government in Department of Personnel & Training.

(2) On the appointed day the authorised strength of the posts in the Senior Principal Private Secretary Grade and the Ministries or Departments to whom these rules apply shall be as specified in Schedule I.

Provided that after the appointed day the authorised strength of posts in the Senior Principal Private Secretary Grade and Ministries and Departments to whom these rules apply shall be such as may, from time to time, be determined by the Central Government in the Department of Personnel & Training.

(3) The scale of pay attached to the Senior Principal Private Secretary Grade shall be Rs. 12000-375-16500.

4. **Method of Recruitment and eligibility.**—(1) Recruitment to the posts of the Senior Principal Private Secretary shall be made by promotion through selection by merit of officers who have rendered five years of approved service in Private Secretary Grade 'A' (pay scale Rs. 10000—15200).

5. **Constitution of Departmental Promotion Committee.**—(1) The Department of Personnel and Training, Government of India shall, from time to time, constitute a Departmental Promotion Committee, consisting of following :

(a) The Chairman or Member of Commission—Chairman

(b) Additional Secretary in the department of Personnel and Training incharge of Central Secretariat Stenographers' Service—Member

(c) Two other Additional Secretaries in the Government of India—Members

(2) The Chairman or as the case may be, the Member of Commission shall preside all meetings of the Departmental Promotion Committee.

6. Appointments to the Senior Principal Private Secretary.—Appointments to the Senior Principal Private Secretary Grade shall be made by the appointing authority in the order in which the names of the officers appear in the select list for the time being in force.

7. Preparation of Lists.—

(1) The Department of Personnel and training in the Central Government shall prepare a centralised seniority list of Private Secretary Grade 'A' (Rs. 10000-15200) on the basis of Select List of that Grade.

(2) The Departmental Promotion Committee shall meet as and when required for preparing a select list of officers to fill the vacancies in the grade of Senior Principal Private Secretary after following the procedure to be observed by Departmental Promotion Committees as laid down by the Central Government from time to time.

8. Maintenance of the Select List.—(1) Subject to the provisions of these rules, an officer included in the Select List shall continue to be included therein till he is appointed to the Senior Principal Private Secretary Grade.

(2) Officers included in the Select List who cannot be appointed to the Senior Principal Private Secretary Grade or, who are reverted therefrom for want of vacancies shall notwithstanding anything contained in rule 9, continue to be included in the Select List and retain the seniority assigned to them in the Select List.

9. Removal of name from the Select List.—The names of persons of the following categories shall be removed by the Department of Personnel and Training from the Select List :—

- (a) persons appointed as Senior Principal Private Secretary;
- (b) persons transferred to any other service or posts;
- (c) persons who die, retire from service or whose services are otherwise terminated.

10. Regulations.—The Central Government in the Department of Personnel and Training may make regulations not inconsistent with these rules to provide for all matters for which provision is necessary or expedient for the purposes of giving effect to these rules.

11. Disqualification.—No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

12. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

13. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of the age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

14. Interpretation.—Where a doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules and the regulations made thereunder the matter shall be referred to the Central Government in Department of Personnel and Training whose decision thereon shall be final.

[No. 10/02/99-CS-II]

757GT/2000-2

KARAN SINGH, Director (CS)

SCHEDULE I

[(See Rule 3(1))]

A. Authorised Strength—58

B List of participating Ministries and Departments, which also includes their participating offices of CSSS.

Sl. No.	Ministry/Department
1.	Department of Agriculture and Co-operation
2.	Ministry of Civil Aviation.
3.	Ministry of Coal.
4.	Ministry of Commerce.
5.	Department of Company Affairs.
6.	Department of Consumer Affairs.
7.	Ministry of Defence.
8.	Department of Education.
9.	Ministry of Environment & Forests.
10.	Department of Expenditure.
11.	Department of Fertilizers.
12.	Department of Food & Civil Supplies.
13.	Ministry of Health & Family Welfare.
14.	Ministry of Home Affairs.
15.	Department of Industrial Policy & Promotion.
16.	Ministry of Information and Broadcasting.
17.	Ministry of Labour
18.	Department of Legal Affairs.
19.	Department of Mines.
20.	Ministry of Petroleum & Natural Gas.
21.	Planning Commission.
22.	Department of Posts.
23.	Ministry of Power.
24.	Ministry of Rural Areas & Employment.
25.	Ministry of Science & Technology.
26.	Ministry of Social Justice & Empowerment.
27.	Department of Steel.
28.	Department of Supply.
29.	Ministry of Surface Transport.
30.	Department of Telecommunication.
31.	Union Public Service Commission.
32.	Ministry of Urban Affairs & Employment
33.	Ministry of Water Resources.